उदीयमान एशिया में भारत*

या. वे. रेड्डी

निहोन कीजाई शिम्बन इन्को (निक्की) द्वारा 'एशिया का भविष्य' विषय पर आयोजित 12वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में आमंत्रित किए जाने पर मैं गौरवान्वित हुआ हूँ। आयोजकों द्वारा इस सत्र के विषय का चयन 'भारत-नये आर्थिक पावर हाउस का उदय' भारत के आर्थिक कार्यनिष्पादन और भविष्य के लिए संभावनाओं में विश्व के विश्वास का संकेतक है। तथापि केंद्रीय बैंकर के रूप में पारदर्शिता और विश्वसनीयता रखते हुए मुझे अपने व्याख्यान में संतुलित और विनम्र रहने की जरूरत है। अतः मैं सम्मेलन के समग्र विषय के सार अर्थात 'भारत का भविष्य' से विषय लेते हुए नई सहस्त्राब्दि में उभरते एशिया की खुलती हुई वृद्धि की कथा के एक भाग के रूप में भारत पर अपने विचार व्यक्त करूंगा। इस संदर्भ में भारत के हाल के आर्थिक कार्य-निष्पादन पर कुछ मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करना ठीक होगा। मैं मध्यावधि में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए दृष्टिकोण और चुनौतियों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के आकलन को भी प्रस्तुत करूंगा। इस सभा के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 'आसानी से अपरिमाणनीय' शक्ति के कुछ स्रोतों का उल्लेख करना भी रुचि का विषय होगा। मैं अपनी बात विकसित होते हुए भारतीय-जापानी आर्थिक सम्बंधों के उल्लेख के साथ करूंगा।

भारत, उदीयमान एशिया तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था

उदीयमान एशिया[1] विश्व जनसंख्या का 45 प्रतिशत और विश्व सघउ का लगभग 11 प्रतिशत बैठता है, हालांकि पीपीपी की दृष्टि से सघउ का अंश लगभग 27 प्रतिशत बैठता है। तथापि हाल के वर्षों में मजबूत वृद्धि को देखते हुए उदीयमान एशिया ने सघउ में वैश्विक वृद्धि के लगभग आधे का योगदान किया है। उदीयमान एशिया में, सघउ की 2004 और 2005 के दौरान क्रमशः 0.4 प्रतिशत और 8.3 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि प्रभावशाली रही। यह मानते हुए कि इसी अवधि में विश्व अर्थव्यवस्था में वृद्धि क्रमशः 5.3 प्रतिशत तथा 4.8 प्रतिशत थी। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष के अनुसार उदीयमान एशिया में वृद्धि की यह गति 2006 में भी जारी रहने की संभावना है। और इस क्षेत्र में वास्तविक सघउ 8.0 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्था वर्ष 2006 के लिए 4.8 प्रतिशत बैठती है।

नयी सहस्त्राब्दि के प्रारम्भ से उदीयमान एशिया के सबल कार्य-निष्पादन के साथ-साथ अमेरिका की निरंतर गतिशीलता ने चालू विश्वव्यापी विस्तार को बनाए रखने में सहायता की है, जिसने यूरोप और जापान की मंदी का भी प्रतिसंतुलन किया। गत दो वर्षों में विश्व की सर्वाधिक तेज वृद्धिवाली अर्थव्यवस्थाएं होने के कारण चीन और भारत ने एशियाई वृद्धि में 73 प्रतिशत का और विश्व सघउ वृद्धि में 38 प्रतिशत का योगदान किया (वर्ल्ड इकॉनोमिक आउटलुक आइएमएफ सितंबर 2005)। यदि जापान में आर्थिक गतिविधियों की वर्तमान वहाली मजबूत हो जाती है, तो जापान एशिया और वैश्विक अर्थव्यवस्था वृद्धि के लिए एक और इंजिन हो जाने की आशा है।

कुछ आलोचक एशियाई उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं को पुनः उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं कहना ज्यादा पसंद करते हैं। यह स्पष्ट करने के लिए कि वस्तुतः उक्त तीन देशों के आर्थिक इतिहास को देखें तो एशिया की ओर धन का मोड़, जो अब हो रहा है, कोई अभूतपूर्व स्थिति नहीं है। ओईसीडी प्रकाशन के अनुसार, 1700 में विश्व सघउ में भारत का अंश 24.4 प्रतिशत था, जबकि चीन का 22.3 प्रतिशत था। संपूर्ण एशिया (जिसमें जापान भी शामिल है) ने 1700 में 61.7 प्रतिशत का योगदान किया जो 1820 में गिरकर 59.2 प्रतिशत और 1998 में 37.2 प्रतिशत तक बढ़ने से पहले 1950 में गिरकर 18.5 प्रतिशत के न्यून स्तर पर आ गया था। (मेडिसन ऐन्गुस 'दि वर्ल्ड इक़ॉनामि : ए मिलेनियम प्रोस्पेक्टिव' ओईसीडी 2001)। 20वीं शताब्दि के उत्तरार्द्ध में यह पुनरुत्थान जापान द्वारा प्रेरित था, जो पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के चमत्कार से सफल हुआ था। इसके बाद चीन की असाधारण सफलता और वर्तमान में वृद्धि और स्थिरता इन दोनों ही दृष्टियों से भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रभावशाली कार्यनिष्पादन है। विश्व बैंक के विश्व विकास के संकेतकों के अनुसार

* 25 मई 2006 को टोकियों में निहोन कीजाई शिम्बन, इन्को (निक्की) द्वारा 'एशिया का भविष्य' - दि रोड टू एन 'एशियन कम्यूनिटी' - संकल्पनाएं और संभावनाएं विषय पर आयोजित 12वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. या.वे.रेड्डी का व्याख्यान।

1 एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय आर्थिक दृष्टिकोण (मई 2006) में अंतरर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अपनाई गई परिभाषा के अनुसार उदीयमान एशिया से तात्पर्य है - चीन, भारत, हांगकांग एसएआर, कोरिया, सिंगापुर, चीन का ताइवान प्रान्त, इन्डोनेशिया, मलेशिया फिलीपीन्स तथा थाईलैंड।

भारत का स्थान अमरीका, चीन और जापान के बाद चौथा आता है यदि क्रय शक्ति समानता (पीपीपी) के आधार पर इन अर्थव्यवस्थाओं के आकार को मापा जाए। यह जानना रोचक होगा कि क्रय शक्ति समानता की दृष्टि से विश्व की चार सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से तीन एशिया में हैं।

हाल के वर्षों में एशियाई अर्थव्यवस्थाएं भारत के प्रमुख व्यापार सहभागियों के रूप में उभर रही हैं। भारत का व्यापार इसकी समग्र व्यापार वृद्धि की तुलना में इन देशों के साथ तेजी से बढ़ा है। 2004-05 में भारत के कुल निर्यातों में इन उदीयमान एशियाई अर्थव्यवस्थाओं का अंश 22.4 प्रतिशत (1999-2000 में 16.0 प्रतिशत) तथा भारत के कुल आयातों में इन देशों से आयातों का अंश 20.1 प्रतिशत बैठता है। 2004-05 में चीन अमरीका के बाद भारत के लिए दूसरा प्रमुख निर्यात गंतव्य देश था और अब यह भारत के लिए आयातों का सबसे बड़ा स्रोत हो गया है जिसमें उसने अमरीका को भी पीछे छोड़ दिया है। चीन के निर्यात 2004-05 में 81 प्रतिशत बढ़े, जबकि चीन से आयातों में 67 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो इन दोनों देशों के बीच बढ़ते हुए व्यापार संबंधों को दर्शाता है। ऐसी ही प्रवृति एशियान-5 (सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपीन) की तुलना में देखी गई। परंतु आगे जाकर इन देशों के साथ व्यापार में विस्तार की भारी संभावनाएं हैं। एक प्रकार से हाल के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था का बाह्य क्षेत्र के प्रति बढ़ती हुई खुलेपन की नीति शेष एशिया के साथ इसके बढ़ते हुए व्यापार संबंधों को दर्शाती है। भारत के विदेश व्यापार में एशियाई देशों की बढ़ती हुई महत्ता को मानते हुए, अंकित और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर पर भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा जारी सूचकांकों को संशोधित किया गया है ताकि उसमें चीन के रिंमिबी और हांगकांग के डालर को भी भारांक योजना में शामिल किया जा सके। जापान को पहले ही इसमें शामिल कर लिया गया था। अतः एशियाई अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व कुल छह में से तीन का हो गया है।

भारत के कार्य-निष्पादन की मुख्य-मुख्य विशेषताएं

नवम्बर 2005 में मिनिस्टर मेंटर ली कुआन यीव जो व्यापक रूप से प्रशंसा-प्राप्त सिंगापुर के पूर्व प्रधान मंत्री हैं, ने 37 वें जवाहर लाल स्मारक व्याख्यान में कहा था :

> ''जब 2000 में अपने संस्मरणों का दूसरा खंड प्रकाशित किया था तो मैंने लिखा था भारत एक पूरी न की गई महानताओं का देश है। इसकी क्षमताओं को पूरीतरह से प्रयोग में नहीं लाया गया है।''
>
> अब मैं अपने विचारों को संशोधित करके प्रसन्न हूँ। ''विश्व में भारत के स्थान के बारे में नेहरू जी के विचार और भारत के विश्व खिलाड़ी बनने के सपने अब भारत की पकड़ के अंदर हैं''

जहाँ गत पांच वर्षों में भारत में हुआ परिवर्तन नाटकीय दिखता है, वस्तुतः यह असतत नहीं है। प्रथम, एक राष्ट्र के रूप में भारत सोच समझकर पिछली आधा शताब्दी से उन सपनों को साकार करने का कार्य कर रहा है कि जो उसने अपनी आजादी के समय देखे थे। दूसरे, 1980 के दशक के घरेलू विनियमन और 1990 के दशक के आर्थिक उदारीकरण ने इस वृद्धि को तेज करने में मदद की। तीसरे शायद, विश्व भारत और इसकी प्रगति को पहले से ज्यादा अच्छी तरह से समझ रहा है।

जैसा कि अनेक विश्लेषकों ने उल्लेख किया है 1980 से 2000 की अवधि के बीच भारत के आर्थिक कार्य-निष्पादन की तीन मुख्य विशेषताएं हैं - प्रति व्यक्ति उत्पाद की उच्च वृद्धि जो केवल चीन और पूर्व एशियाई देशों में ही ज्यादा हुई है। एक बहुत स्थिर प्रतिव्यक्ति उत्पाद जो चीन और पूर्व एशियाई से भी ज्यादा है, तथा इस वृद्धि का स्रोत कुल कारक उत्पादकता में वृद्धि का रहा है जिसका पूंजी पर केवल बेहतर प्रतिलाभों द्वारा प्रेरित होने के बजाए प्रक्रिया की दीर्घकालीन प्रकृति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

भारतीय अर्थव्यवस्था अभी हाल के वर्षों में उच्चतर स्तर की वृद्धि के पथ पर बढ़ी हुई लगती है, जिसमें वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की औसत वार्षिक वृद्धि 1980 के दशक की 5.8 प्रतिशत से बढ़कर 1992-93 से 2005-06 तक की अवधि के दौरान 6.3 प्रतिशत हो गई। बाद में यह अर्थव्यवस्था पुनः वृद्धि की तेज गति पकड़ती हुई-सी लगती है जो पिछले तीन वर्षों में औसत सघउ में लगभग 8 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्शाती है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मुद्रास्फीति की स्थितियां संतुलित होकर लगभग 5 प्रतिशत पर आ गयी हैं जो पहले की अवधियों की अपेक्षाकृत काफी उच्च स्तरों से उल्लेखनीय रूप से गिरी हैं।

हाल के वर्षों में आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने में सकल घरेलू निवेश की दरों में लगातार वृद्धि से सहायता मिलती रही है जो 2001-02 के सघउ के 23.0 प्रतिशत से बढ़कर 2004-05 में 30.1 प्रतिशत हो गई, साथ ही पूंजी का दक्षतापूर्ण उपयोग भी बढ़ा है। इसी अवधि में सकल घरेलू बचत दर भी 26.5 प्रतिशत से बढ़कर 29.1 प्रतिशत हो गई है। भारत में बचत-निवेश संतुलन एक वांछित दायरे में है इस प्रकार यह भी वैश्विक स्थिरता में योगदान कर रही है।

इन सुधारों से सुविधा-प्राप्त वित्तीय बाजार अधिक स्वतंत्र और संस्थाएं कार्य परिचालन की दृष्टि से अधिक आजाद हो गई हैं। मौद्रिक नीति ने अधिक परिचालनगत स्वायत्तता प्राप्त कर ली है, जिसमें 1997 से घाटे का स्वतः मौद्रीकरण बंद हो गया है और भारतीय रिज़र्व बैंक इस वित्त वर्ष से प्राथमिक गिल्ट नीलामियों से बाहर निकल आया है, साथ ही अप्रत्यक्ष लिखतों पर उत्तरोत्तर निर्भरता बढ़ती जा रही है। अनेक बाजार व्यवस्थित और स्थिर हैं, जिनमें सहभागी प्रतिभूति कृत घटकों की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं और दरें आम तौर पर नीतिगत उद्देश्य में यथा निर्धारित दायरे में घटबढ़ रही हैं। सरकारी प्रतिभूति बाजार अब गहन और ऊर्जस्वित हैं,

जिसमें भिन्न-भिन्न प्रकार की लिखतें हैं जो विभिन्न निवेशकों की विभिन्न मांगों की पूर्ति कर रही हैं। विदेशी मुद्रा बाजार ने गहनता प्राप्त कर ली है। जबकि पूंजी बाजार व्यापारिक प्रक्रियाओं जोखिम प्रबंधन तथा भुगतान और निपटान प्रणाली में परिपक्व हो गए हैं। शेयर मार्केट के पूंजीकरण की दृष्टि से भारत तीन सबसे बड़े उभरते हुए बाजारों में से एक है। इनमें लगभग 9000 सूचीबद्ध कंपनियां हैं जिनमें से लगभग 100 कंपनियों में से प्रत्येक का बाजार मूल्य 1 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक का है। विदेशी निवेश 1000 से अधिक कम्पनियों में फैला है जो एक प्रभावशाली रिकार्ड है।

बैंकिंग क्षेत्र हाल के वर्षों में सुदृढ़ हुआ है जहां तक यह सुदृढ़ विवेकसम्मत विनियमन और संचालन मानकों का संबंध है। और इसप्रकार जोखिमों को न्यूनतम किया गया है, प्रकटीकरण सुदृढ़ हुआ है तथा परिचालनगत दक्षता में सुधार हुआ है। बैंक अब बासल II मानदण्डों की ओर बढ़ रहे हैं तथा क्षतिग्रस्त ऋणों को सीमित करने के लिए उपाय कर रहे हैं। वित्तीय मध्यस्थकों के स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार हुआ है तथा प्रतिस्पर्धा और दक्षता में भी उल्लेखनीय रूप से सुधार हुआ है, साथ ही उसमें स्थिरता तथा आघातों के प्रति जूझने की शक्ति बढ़ी है।

उदारीकरण की यशस्वी और क्रमबद्ध रणनीति से लाभान्वित होकर, भारत का बाह्य क्षेत्र और अधिक ऊर्जस्वित हो गया है। जहाँ चालू खाता घाटा 2003-04 तक लगभग तीन वर्षों तक अधिशेष में रहने के पश्चात 2004-05 में मामूली-से और वहनीय घाटे में बदल गया । पूंजी खातें में उल्लेख शक्ति आई जिसके फलस्वरूप विदेशी मुद्रा भण्डार में निरन्तर वृद्धि जारी रही । वर्तमान में, भारत का विदेशी मुद्रा भण्डार इसके बाह्य ऋणों से ज्यादा का हो गया है, अतः इसके द्वारा अर्थव्यवस्था की बेहतर ऋण शोधन क्षमता को दर्शाता है।

हाल के वर्षों में विनिमय दर नीति सावधानीपूर्वक निगरानी तथा नमनीयता के साथ विनिमय दरों के प्रबन्धन के व्यापक सिद्धांतों द्वारा निदेशित होती रही है जिसका कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है या पहले से ही घोषित लक्ष्य या कोई बेंड नहीं है। जहां अंतर्निहित मांग और आपूर्ति की स्थितियों द्वारा विदेशी मुद्रा विनिमय दरों के घटबढ़ निर्धारण की अनुमति देते हुए एक समय तक विनिमय दर में व्यवस्थित रूप से घटबढ़ हुई। रिज़र्व बैंक तीव्र उतार-चढ़ाव को सीमित रखने के लिए बाजार में हस्तक्षेप करता है। उभरते हुए बाजारों में अर्थक्षम विनिमय दर रणनीति पर हाल ही में हुई अंतरराष्ट्रीय शोध ने भारत द्वारा अपनाई गई विनिमय दर नीति का पर्याप्त समर्थन किया है।

विश्व में कार्यरत भारतीय फर्मों ने नए आयाम प्राप्त किए हैं। सॉफ्टवेयर सेवाओं में अपनी अग्रणी हैसियत के अलावा, भारत विनिर्माण और विनिर्मित उत्पादों के निर्यात के लिए भी एक प्रमुख केंद्र बन रहा है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, सीमापार के अधिग्रहण अपतटीय ठेकों को पाने तथा अन्य निम्न लागत वाले स्थलों में सहज वृद्धि के साथ विश्व व्यापी होता जा रहा है। इसके साथ ही साथ विश्व के प्रमुख खिलाड़ी भारत में अपनी अपतटीय सुपुर्दगी क्षमताओं को निरंतर उन्नत बनाते जा रहे हैं। अपनी पैतृक कंपनी तथा अधिग्रहीत कंपनी की क्रियाविधि गत एकरूपता (सहक्रियाओं) का प्रयोग करते हुए तथा प्रमुख बाजारों के समीप उत्पादन सुविधाएं रख कर भारतीय फार्में भी विदेशी स्थलों पर अपनी प्रतिस्पर्धी बेहतर स्थिति को बढ़ाने के लिए, विदेशों में विनिर्माण कम्पनियों का अधिग्रहण कर रही हैं।

दृष्टिकोण तथा चुनौतियां : केंद्रीय बैंक की दृष्टि में

एक माह पहले (18 अप्रैल 2006 को) जारी वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक नीति संबंधी वक्तव्य अर्थव्यवस्था के लिए दृष्टिकोण का भारतीय रिज़र्व बैंक का आकलन प्रस्तुत करता है। नीति संबंधी वक्तव्य में यह कहा गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अनेक निम्नमुखी जोखिम मंडरा रहे हैं जिनका भारत जैसे देश के लिए, जिसके लिए वैश्विक समेकन के चैनल समय के साथ-साथ कठोर होते जा रहे हैं, मध्यावधि के लिए संभावनाओं के निहितार्थ हैं - उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए प्रमुख वैश्विक जोखिम, अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल मूल्यों में बढ़ने की संभावना, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के व्यापक आर्थिक असंतुलनों के अव्यवस्थित रूप में फैलने का जोखिम और अंतरराष्ट्रीय ब्याज दरों का कठोर होना। हालांकि इसमें निम्नमुखी होने के जोखिम भी विद्यमान हैं, फिर भी मध्यावधि में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए संभावनाएं कमोबेश सकारात्मक हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए विकसित होते हुए आर्थिक और कारोबारी परिवेश ऐसे अनेक उत्साहवर्धक संकेत देते हैं जो हाल में देखी गई प्रचुर आर्थिक वृद्धि के पुनः सबल होने का सुझाव देते हैं।

पहला, सकल घरेलू बचत दर में वृद्धि होकर यह लगभग 30 प्रतिशत के स्तरों पर पहुँच गई है। साथ ही सघउ के 2 प्रतिशत तक की बाह्य बचतों को भी खपा रही है, जो तेज गति की वृद्धि दर के पथ को प्राप्त करने के लिए क्षमता प्रदान करेगी।

दूसरे, वर्षों से शुरू किए गए व्यष्टिगत संरचनात्मक सुधारों ने इस योग्य बना दिया है कि वास्तविक क्षेत्र में उत्पादकतागत लाभों को जारी रखा जा सकेगा।

तीसरे, वित्तीय क्षेत्र को व्यापक और गहन बनाने में शामिल सुधार की प्रक्रिया तथा साथ ही बेहतर विनियमन और पर्यवेक्षण ने भी उत्साहजनक परिणाम दर्शाए हैं । जैसा कि इस क्षेत्र के लिए संगत उत्पादकता उपायों में दिखलाई देते हैं।

चौथे, विभिन्न कारोबारी प्रत्याशागत सर्वेक्षणों द्वारा मापे गए वृद्धिशील कारोबारी विश्वास तथा निवेश परिवेश में सुधार के साक्ष्य हैं। इसके साथ-साथ बढ़े हुए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के संकेत भी हैं।

पांचवें, सर्वाधिक प्रगतिशील और गतिशील भारतीय कंपनियां अधिग्रहणों तथा उच्चतर बाहर जाने वाले विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के माध्यम

से विश्व में अपनी उपस्थितियों के बढ़ते हुए स्तरों को दर्शा रही हैं। इस प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से प्रमुख (डोमेन) ज्ञान की प्राप्ति तथा सर्वोत्तम संव्यवहारों वाला कारोबारी ज्ञान, तथा विपणन में प्रचुरताजन्य मितव्ययिता भारतीय कारोबार की उत्पादकता वृद्धि को तेज कर सकती हैं।

अंन्तिम, यह उल्लेखनीय है कि भारतीय कारोबार बुनियादी संरचना द्वारा उपस्थित की गई उल्लेखनीय बाधाओं के बावजूद, अधिकांश मापदंडों की दृष्टि से हाल के वर्षों में, प्रभावशील वृद्धिगत कार्यनिष्पादन दर्शाने में सफल रहा है। इसने तेल के मूल्यों में वृद्धि जैसी प्रतिकूल गतिविधियों के साथ बढ़ने की क्षमता की दृष्टि से जिजीविषा दर्शाई है।

मध्यावधिक दृष्टिकोण के लिए इन सकारात्मक कारकों के बावजूद, कुछ महत्वपर्ण मुद्दे भी हैं जिनसे स्थिरता के साथ वृद्धि की वर्तमान गति को बनाये रखने के लिए निपटना भी जरूरी है।

पहला है, भौतिक बुनियादी संरचना की खराब हालत प्रमात्रा और गुणवत्ता-दोनों ही दृष्टियों से, जो व्यवसायी वर्ग तथा नीति निर्माताओं का सही रूप से केंद्रीकृत ध्यान आकृष्ट कर रही है। इनका परिणाम संतोषजनक होगा ऐसी आशा करने के कुछ कारण हैं। बशर्ते विनियामक ढांचों में सुधार लाने जारी रखी जाएं। वर्तमान निवेश मांग से प्रेरित है और इसलिए उनका कम से कम इंतजार की अवधि में पूरा होने की संभावना है। साथ ही पूरा होने पर वे तेजी से प्रतिलाभ भी देंगे। प्रौद्योगिकीगत गतिविधियों तथा घरेलू निर्माण क्षमताओं का तेजी से विस्तार उस त्वरित और दक्ष कार्यान्वयन की गति को और तेज करेगा। घरेलू वित्तीय क्षेत्र के स्वस्थ बुनियादी तत्वों को तथा विदेशी निवेशकों के बढ़े हुए विश्वास को देखते हुए निधियन में कोई गम्भीर समस्या नहीं आनी चाहिए।

दूसरे, केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर राजकोषीय समेकन हो रहा है और व्यापक दिशा निदेशों पर अब कहीं ज्यादा सहमति है। केंद्र सरकार को हाल का बजट समेकन को सही पथ पर ले आया है, जिसमें सकल राजकोषीय घाटे को 2009 तक सघउ के 3 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा गया है । साथ ही साथ राजस्व के (चालू) घाटे को समाप्त करने का लक्ष्य है। राज्यों के वित्त पर भारतीय रिजर्व बैंक में हमारे अध्ययन उनके राजकोषीय स्वास्थ्य के संबंध में आशावाद को आधार प्रदान करते हैं तथापि पावर की सब्सिडी तथा सेवाओं की सुपुर्दगी में गुणवत्ता को सुनिश्चित करना, विशेषकर शिक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में समाधान निकालने की जरूरत है।

तीसरा और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दा कृषि के विकास से जुड़ा है। जहाँ अधिकांश श्रमिक-शक्ति कृषि पर निर्भर है, वही कृषि से तैयार की गई सघउ की वृद्धि दर जनसंख्या की वृद्धि दर से मामूली-सी ऊपर है। जबकि कृषि से इतर क्षेत्र की वृद्धि दर सुदृढ़ है जो गरीबी के त्वरित उन्मूलन के लिए पर्याप्त नहीं है। कृषि में और तेज गति से वृद्धि को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से, वैधानिक, संस्थागत और रवैयागत परिवर्तन लाने की जरूरत है ताकि वह आवश्यक बढ़े हुए सार्वजनिक और निजी निवेश को बढ़ाने में और सहायक हो सके। रिज़र्व बैंक अपनी ओर से ग्रामीण सहकारी ऋण प्रणाली को पुनः सशक्त बनाने के लिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सुदृढ़ करने में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निवेशों को बढ़ाने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को प्रोत्साहित करने में तथा उचित कीमत पर और समय पर पर्याप्त ऋण की सुपुर्दगी सुनिश्चित करने में अपने प्रयासों को दुगुना कर रहा है। वस्तुतः हम विधान का तथा गैर संस्थागत धन उधार देने जो कि किसानों के लिए अभी भी ऋण का उल्लेखनीय स्रोत बना हुआ है, के कार्यान्वयन का अध्ययन कर रहे हैं।

भले ही भारतीय अर्थव्यवस्था उच्चतर वृद्धि पथ पर बढ़ रही है, फिर भी बेरोजारी को कम करने के लिए उल्लेखनीय सुधार किए जाने बाकी हैं। आवधिक सर्वेक्षणों पर आधारित अध्ययनों के अनुसार, ग्रामीण और शहरी इन दोनों क्षेत्रों में, 1994 से 2004 की अवधि के दौरान बेरोजगारी की दर बढ़ी है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की दरों में तेजी से वृद्धि, कृषि में मंदी को दर्शाती है। तथापि, एक सकारात्मक विशेषता यह रही है कि गरीबी अनुपात में कमी आई है, जो 1993-94 के 36.0 प्रतिशत से घटकर 1999-2000 में 26.1 प्रतिशत पर आ गया है। भारत सरकार ने लक्ष्य बनाया है कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के अनुपात को 2012 तक 10 प्रतिशत तक ले आया जाए। जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स (एनडीजी) के अंतर्गत राष्ट्रसंघ द्वारा अपनाए गए लक्ष्य के अनुरूप है।

आसानी से मापी न जा सकने वाली शक्तियां

भारत के भविष्य के वैश्विक आकलन की एक उललेखनीय विशेषता भारत की उन शक्तियों के बारे में बेहतर जागरूकता और उनका सुस्पष्ट प्रयत्न है जिनको आसानी से मापा नहीं जा सकता, परंतु जो दीर्घावधि संभावनाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। मैं आपका ध्यान संक्षेप में उनमें से कुछ की ओर आकृष्ट करना चाहूँगा, यह आवश्यक नहीं है कि मैं भी उनकी पुष्टि करता हूँ।

सामाजिक संदर्भ में आमतौर पर लिखित और मौखिक रूप में अंग्रेजी भाषा में भारतीयों की दक्षता की बेहतर स्थिति पर ध्यान दिया गया है। तथापि इस अंतर्निहित शक्ति को भारत की भाषायी विविधता की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए जो लोगों को अपनी मातृभाषा के अलावा कई भाषाओं की सीखने के लिए प्रेरित करती है। (भारत के संविधान के अनुसार 23 राष्ट्रीय भाषाएं हैं)। अनेक भाषाओं के साथ बढ़ा हुआ परिचय न केवल देश में समेकन लाने में सहायता करता है, बल्कि उन्हें बहु-संस्कृति वाली स्थितियों के साथ आत्मसात हो जाने को भी तैयार करता है। उदाहरण के रूप में, फाइनेंसियल टाइम्स में हाल में छपी रिपोर्ट (लेखक पीटर मार्च,

दिनांक 17 मई 2006) जिसका शीर्षक था - 'चलायमान श्रमिक शक्ति का पर्व' जिसमें लिखा है -

> ''भारत में एक गुमनाम कार्यालय में जे-टीम भारत और जापान के बीच संपर्कों को मजबूत करने के मिशन पर है। एच.बी.जयन्ती 60 इंजीनियरों के समूह के मुखिया हैं जो योजागावा, जापानी औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली बाजार, बंगलौर के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्हें जापानी बोलने ही नहीं, बल्कि जापानी में सोचने के लिए भी प्रशिक्षित किया गया है ताकि वे उत्पाद विकास पर सहयोग करते हुए जापान में अपने सहयोगियों के साथ प्रभावी रूप से अपनी बात संप्रेषित कर पाते हैं''।

इस संबंध में महिलाओं के सशक्तीकरण की महत्ता को स्वीकार करना भी महत्वपूर्ण है। मैं अपने राज्य आंध्र प्रदेश से कुछ संगत तथ्य प्रस्तुत करना चाहूँगा। वहाँ मेडिकल कालेजों में प्रवेश के लिए महिलाओं के लिए न्यूनतम एक तिहाई सीट आरक्षित हैं, परंतु अब आधे छात्र लड़कियां हैं। आंध्र प्रदेश में 92,000 छात्र इस वर्ष इंजीनियरिंग में भर्ती किए गए जिनमें से 30,000 से ज्यादा लड़कियां हैं। इसी प्रकार राजनीति में भी महिलाओं का अच्छा प्रतिनिधित्व है। स्थानीय निकायों में ग्राम पंचायत (ग्राम स्तर पर चुनी गई स्वयं की सरकार) के सदस्यों से लेकर महानगरों के मेयरों तथा जिला परिषदों के (जिले के स्तर पर चुनी गई परिषद) अध्यक्ष तक लगभग 2,50,000 चुने हुए पदाधिकारी हैं और इनमें से 85,000 से अधिक महिलाएं हैं। ऐसे ही गतिविधियां जो अन्य राज्यों में भी हो रही हैं भविष्य के लिए महिलाओं के सशक्तीकरण के दृष्टिकोण को सकारात्मक दिशा प्रदान करती हैं।

इन सबसे बढ़कर स्वतंत्र प्रेस का अस्तित्व है जो ज्यादतियों के विरूद्ध सुरक्षा का आश्वासन प्रदान करती है तथा वह सरकार को सभी स्तरों पर अन्य किसी रूप की अपेक्षा अधिक जबावदेह बनाती है। इस संबंध में यह ध्यान देना रुचिकर होगा कि जहाँ 17 अंग्रेजी समाचार पत्रों की संयुक्त वितरण संख्या 6.3 मिलि. और उसके पाठकों की संख्या 17.9 मिलि. है, वहीं भारत में देशी भाषाओं के 54 अग्रणी अखबार हैं जिनकी वितरण संख्या 21.4 मिलि. और उनके पाठकों की संख्या 197.2 मिलि. है।

राजनैतिक परिवेश मिलेजुले मंत्रिमंडलों और केंद्र और कई राज्यों दोनों स्तरों पर समय-समय होने वाले चुनावों के बावजूद राजनैतिक प्रणाली की स्थिरता से जाना जाता है। यह उल्लेखनीय है कि राजनैतिक हलकों ने प्रशंसित आर्थिक सुधारों की प्रगति को बाधा नहीं पहुँचाई है। जैसा कि जॉन हॉपकिन विश्वविद्यालय, वाशिंगटन के प्रजातंत्र के विशेषज्ञ माइकिल मंडेलबम ने कहा था -

> ''भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी सतह पर काफी उथल-पुथल है, परंतु वहाँ की राजनैतिक प्रणाली के आधार तल में गहरा मतैक्य है।''

वस्तुतः राजनैतिक प्रणाली को दीर्घावधिक पूर्व अनुमेयता की दृष्टि से वैश्विक कारोबार को सुविधाजनक बनाना चाहिए। भारत में जापान के राजदूत यासुकुकी इनोकी ने ऐसा कहा बताते हैं कि -

> ''अगले दो दशकों के लिए भारतीय समाज पूर्व-अनुमेय है, और लोकतांत्रिक ढांचा भी पूर्व-अनुमेय है।''

जहाँ तक व्यापक अर्थव्यवस्था का संबंध है ऐसी सर्व-सम्मति बढ़ती जा रही है कि भारत ने सुधारों की देहली को पार कर लिया है और वह वस्तुतः बाजारोन्मुखी और मूल्य आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। इस स्थिति ने देश को विश्व के लिए एक सेवा-की आउटसोर्सिंग के केंद्र के रूप में उभरने में मदद की है। इसके अलावा वृद्धि की गति में आयी तेजी घरेलू मांग के विकसित होते हुए स्वरूप को देखते हुए बने रहने की आशा है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (नेशनल कांउसिल ऑफ एंप्लाइड इकॉनामिक रिसर्च) (एनसीएईआर) मिश आंकड़ा स्पष्ट संकेत करते हैं कि

> ''भारत अत्यधिक रूप से धनी हो रहा है। इस दशक के अंत तक देश की जनसंख्यागत संरचना बदल जाएगी जो उसकी अंतर्मुखी पिरामिड की संरचना से जिसमें एक छोटी-सी धनिक वर्ग होता है और काफी बड़ा अल्प आय वाला वर्ग होता है, एक बिना तराशे गए हीरे वाली संरचना में बदल जाएगी जिसमें अल्प आय वाला उल्लेखनीय भाग ऊपर की ओर बढ़ता है और मध्यम वर्ग का अंग बन जाता है।''

इसके अलावा, 2010 और 2040 के बीच जनसंख्यागत बोनस मिल सकता है, भारत की कार्य करने वाली जनसंख्या अभी भी बढ़ रही है, जबकि शेष एशिया की जनसंख्या स्थिर हो रही है या गिर रही है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक और निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धा करते हुए एक गतिशील संतुलन में साथ-साथ चल रहे हैं जो कि देश को प्रतिस्पर्धी शक्ति प्रदान कर रहा है।

अंतिम, कारोबारी परिवेश की दृष्टि से बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था के साथ प्रभावशाली वृद्धि धरातल से ऊपर उठने का अभ्यास कर रही है जिसमें एक काफी व्यापक आधार वाला बढ़ता हुआ उद्यमी वर्ग है। नवोन्मेष करने की क्षमता उच्च मानी गई है और नवोन्मेष की लागत भारत में निम्न बताई गई है। उदाहरण के लिए इंजीनियरिंग-सघन सेवा प्रेरित विनिर्माण कार्य में माल के थोक में उत्पादन के मानक तरीकों के लाभों को संतुलित करने का प्रयास किया जाता है। जैसा कि बताया गया है विनिर्माण में सेवा दृष्टिकोण पर जोर बढ़ रहा है। जिसमें गुणवत्ता को उच्च रखने तथा दक्षता को बढ़ाने के लिए उत्पादन को कम रखा जाता है। ये प्रवृत्तियां शायद भारत में बढ़ते हुए उद्यमी वर्ग के बीच नवोन्मेष करने की अभिरुचि को दर्शाती हैं जिसमें व्यावसायिकता जुड़ी है तथा वे वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी होना चाहते हैं।

बढ़ते भारत-जापानी आर्थिक संबंध

वैश्विक और हमारे परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से एक अग्रणी औद्योगिक अर्थव्यवस्था के रूप में जापान ने वर्षों के दौरान विश्व व्यापार की वृद्धि में उल्लेखनीय योगदान किया है। जापान ने व्यापार और निवेश की दृष्टि से विश्व अर्थव्यवस्था के साथ विकासशील देशों के, विशेषकर उदीयमान एशिया के समेकन के लिए मुख्य भूमिका निभाई है। विकासशील अर्थव्यवस्थाएं जापान के निर्यातों और आयातों की प्रमुख स्रोत रही हैं। 2004 में जापान के कुल निर्यातों और आयातों में इनका अंश क्रमशः 58 प्रतिशत और 65.5 प्रतिशत बैठता है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में उदीयमान एशिया का अंश जापान के निर्यातों और आयातों का लगभग 40 प्रतिशत बैठता है।

भारत और जापान के बीच कई शताब्दियों पुराने सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। हाल की अवधि में इन दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रमुख सुधार होते हुए देखा है। अप्रैल 2005 में जापानी प्रधान मंत्री श्री कोईजुमी के भारत दौरे में इन द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर जोर दिया गया था। इस दौरे ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि आध्यात्मिक घनिष्ठ सम्बंध दीर्घकालीन सांस्कृतिक संबंध तथा राजनीतिक, आर्थिक और कार्यनीतिगत हितों की एक रूपता का उच्च स्तर, वैश्वीकरण की ओर बढ़ते विश्व के साझीदारों के रूप में भारत और जापान को महानशक्ति प्रदान करते हैं। इस साझीदारी को और सशक्त बनाने की दृष्टि से इस दौरे के परिणामस्वरूप एक आठ आयामी पहल शुरू की गई। जापान के साथ उच्च स्तर के सम्पर्कों की गहनता तबसे बनी हुई है और दोनों देशों के प्रधानमंत्री भी क्वालालम्पुर में प्रथम पूर्व एशियाई शिखरकर्ता के द्विपक्षीय मुद्दों पर मिल चुके हैं। अतः पिछले एक साल में हमारे द्विपक्षीय संबंधों में सघन व्यस्तताएं देखी गई हैं जिससे जापान को एशिया में हमारी नीति का मुख्य बिंदु बना दिया है।

भारत और जापान में आर्थिक क्षेत्र में भी एक-दूसरे की पूरक अनेक स्थितियां हैं। जापान अपेक्षाकृत श्रमिक की न्यूनता परंतु पूंजी की बहुलता वाला देश है, जबकि भारत मानव संसाधनों के सम्पूर्ण परिवेश में बहुलता वाला देश है। इसी प्रकार भारत साफ्टवेयर के क्षेत्र में विश्व की मानी हुई हस्ती है और हार्डवेअर के क्षेत्र में दशकों से जापान की शक्ति सुस्थापित है। भारत के पास कच्चा माल और खनिजों के स्रोतों की खान है, और जापान के पास जानकारी सघन विनिर्मित माल बनाने के लिए प्रौद्योगिकी और पूंजी है। संक्षेप में, यदि दोनों देश आर्थिक सहयोग की दृष्टि से और अधिक सघन प्रयास करें तो उनमें सहक्रियाओं की एकरूपता, प्रचुरताजन्य मितव्ययिता और एक दूसरे की पूरकताएं दोनों देशों के भारी कल्याणकारी लाभ की ओर जा सकती हैं।

हाल के वर्षों में जापानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारत में बढ़ती हुई रुचि को दर्शाया है और 2004 के दौरान पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों में एक अच्छी भली संख्या जापानी निवेशकों की है। जापान ने भारतीय प्रतिभूति बाजार में निवेश करने के लिए जापानी निवेशकों से निधियां जुटाने के लिए 'भारत निवेश निधि' शुरू की थी। जेबीआईसी द्वारा जापानी विनिर्माण कंपनियों द्वारा (नवंबर 2004) 'विदेशी कारोबार परिचालन' पर कराए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार चीन और थाईलैंड के बाद भारत तीसरा सबसे उन्नतशील निवेश के लिए गंतव्य देश माना गया था, जबकि इसी प्रकार के 2003 के सर्वेक्षण में उसे 5वीं और 2000 के सर्वेक्षण में उसे 11वां स्थान दिया गया था।

भारत के बढ़े हुए आर्थिक विकास में जापान के सहयोग और सहभागिता को हार्दिक रूप से सराहा गया है। जापान की सहायता खासकर पावर, शहरी परिवहन, शहरी जल आपूर्ति जलमल निकासी, जल प्रबंधन, समुद्री बन्दरगाह, पर्यटन के भौतिक बुनियादी क्षेत्र में तथा पर्यावरण और वन क्षेत्रों में भी सहायक रही है। जापान 1958 से भारत को द्विपक्षीय ऋण और अनुदान सहायता देता रहा है। और जापान भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय सरकारी विकास सहायता का सहभागी है।

सारांश में जापान और भारत के बीच बढ़ते हुए घनिष्ठ संबंध एशिया के सुनहरे भविष्य के लिए तथा विश्व अर्थव्यवस्था में एशिया के लिए एक मजबूत आवाज के रूप में उभरकर आए हैं।

निष्कर्षात्मक टिप्पणियां

भारत में सार्वजनिक नीति से संबंधित तीन प्रश्नों का उत्तर देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। पहला, सार्वजनिक नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है ? प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह के शब्दों में ;

> ''प्रथम और सर्वाधिक प्राथमिकता उस अधूरे कार्य को पूरा करना है जिसे हमारे लोकतंत्र के संस्थापक सदस्यों ने स्वतंत्रता के समय हमारे सामने रखा था, दीर्घकालीन गरीबी, अज्ञान और रोगों से छुटकारा पाना जिन्होंने हमारे लाखों लाखों लोगों को आक्रांत किए रखा है। महान प्रगति की गई है, विशेषकर गत 20 वर्षों में, भारतीय अर्थव्यवस्था ने बहुत अच्छा कार्य किया है। ..... हमें उस वृद्धि को अपनी कृषि में सुदृढ़ वृद्धि द्वारा, अपनी भौतिक और अपनी सांस्कृतिक बुनियादी संरचना में दर्शाने की जरूरत है। ये हमारी मुख्य प्राथमिकताएं हैं।''

दूसरे, वे कौन-से साधन हैं जिनसे ये उद्देश्य प्राप्त किए जा सकते हैं ? संक्षिप्त रूप में रखें तो उनमें शामिल हैं - देश की बुनियादी संरचना - भौतिक, सामाजिक और संचालन का आधुनिकीकरण करके, रोजगार का सृजन करके तथा इस प्रयोजन के लिए विदेशी निवेश को आकर्षित करके।

तीसरा, इस संदर्भ में, वैश्विक प्रबंधकों को लिए, जो भारत के बारे में जानना चाहते हैं, उपयुक्त संदेश क्या है ? इस प्रश्न के बारे में प्रधान

मंत्री मनमोहन सिंह का उत्तर था ;

''भारत का भविष्य युवा समाज बनाने, खुली राजनीति, सभी मौलिक मानव अधिकारों का सम्मान करने वाला एक सुचारू रूप में कार्यरत लोकतंत्र, कानून के शासन को स्वीकार करने वाला और साथ ही साथ एक सफल, अंतरराष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने में निहित है।''